भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †4212
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

भाषिणी परियोजना की एआई अनुवाद प्रौद्योगिकियां

†4212. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहुभाषी ई-गवर्नेंस से ग्रामीण नागरिकों की ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म तक पहुंच किस प्रकार बढ़ने की संभावना है;

(ख) सेवा वितरण में सुधार, भागीदारी बढ़ाने और शासन में स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत की जा रही भाषिणी परियोजना की विशिष्ट एआई अनुवाद प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण नागरिकों को उनकी मातृभाषा में डिजिटल सेवाएं सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा भविष्य में क्या अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन, ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर बहुभाषी सुविधा की शुरुआत का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनकी मातृभाषा में एप्लिकेशन के माध्यम से विचार-विमर्श करने का विकल्प प्रदान करके उनकी पहुँच को बढ़ाना है। इससे नागरिकों की सहभागिता में सुधार, योजनाओं की बेहतर समझ और स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में समावेशी सहभागिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(ख) बहुभाषी क्षमताओं को सक्षम बनाने के लिए, ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की एक पहल, भाषिणी के साथ एकीकृत किया गया है। भाषिणी भारतीय भाषाओं में पाठ और वाक् अनुवाद के लिए अत्याधुनिक एआई/एमएल-आधारित प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीकों का लाभ उठाती है। ई-ग्रामस्वराज के साथ एकीकरण से, सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में सामग्री, प्रपत्रों और अधिसूचनाओं के वास्तविक समय में अनुवाद की सुविधा मिलती है, जिससे सेवा प्रदायगी में सुधार, भागीदारी में वृद्धि और शासन में स्थानीयकरण सुनिश्चित होता है।

(ग) मंत्रालय निरंतर रूप से ई-पंचायत मिश्न मोड परियोजना (एमएमपी) की प्रभावशीलता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर तथा परामर्शात्मक, फीडबैक आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रहा है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और भविष्य के विकास को प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं और हितधारक परामर्शों सहित विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक एकत्र किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों और पंचायत पदाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक को नियमित रूप से शामिल किया जाता है। इन प्रयासों के तहत, मंत्रालय ने हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिमला, हैदराबाद और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए विचार-विमर्श करने और एक रूपरेखा तैयार करने हेतु, मंत्रालय ने नई दिल्ली में उद्योग जगत से परामर्श कार्यक्रम, "मंथन" का भी आयोजन किया। महाराष्ट्र और लखनऊ में भी हितधारकों के साथ विचार विमर्श हुए। इसके अलावा, सक्रिय सहभागिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ कई ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गई हैं। ये बातचीत ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणालीगत सुधार और तर्कसंगतता के लिए कार्रवाई योग्य फीडबैक एकत्र करने में सहायक रही हैं। मंत्रालय भाषा का विस्तार करने, वॉयस बेस्ड इंटरफेस को मज़बूत बनाने और ग्रामीण नागरिकों के लिए उनकी मातृभाषा में डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस तरह के फीडबैक का उपयोग करता है ।

*****